अब आईआईटी भी तैयार करेगा सीईओ

कानपुर (कासं)। जापान और भारत के सहयोग से अगले साल फरवरी में आईआईटी में उच्च कोटि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) तैयार करने के लिए 16 महीने का एक विशेष कोर्स शुरू किया जाएगा। पहले बैच में 50 इंजीनियरों को यह मौका दिया जाएगा। यह कोर्स भारत और जापान के बीच हुए समझौते का एक हिस्सा है।

आईआईटी में जापान के विश्व मैनेजमेंट गुरू के नाम से मशहूर प्रो. शोबी शीबा, आईआईएम कोलकता के निदेशक डा. शेखर चौधरी, सीआईआई की प्रतिनिधि सुनीता नागपाल, जीका के सदस्य काबोशी और आईआईटी के निदेशक डा. संजय गोविंद धांडे ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि आईआईटी में जुलाई 07 से कोर्स को विधिवत् रुप से शुरु कर दिया जाएगा। यह कोर्स केवल व्याख्यान पर आधारित नहीं होगा बल्कि वयवहारिक कौशल प्रशिक्षण (स्किल्ड बेस ट्रेनिगं)पर निर्भर करेगा। उनका कहना था कि देश में ऐसे 250 से अधिक सीईओ तैयार करने का काम शुरू किया गया है। इंजीनियरिंग के ऐसे लोग जो किसी कम्पनी में काम कर रहे हैं और मध्यम उम्र के हैं, साथ ही उन्हें सात-आठ साल का अनुभव है उनका चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। अगर वे इलेक्ट्रानिक या मैकेनिकल फील्ड के होंगे तो बेहतर होगा। इन्हें 15 दिन किसी आईआईटी या आईआईएम में गुजारना होगा लेकिन इसके बाद वे कम्पनियों में जाएंगे और वहाँ विदेश में जाकर भी अनुभव लेंगे। उनका कहना था कि इसके लिए सात माडयूल्स तैयार किए गएं हैं। आईआईटी में चार लैब तैयार की गई हैं। सीआईआई से जुड़ी एक संस्था का हवाला देते हुए कहा कि कुछ ट्रेड सेक्टर चुने गए हैं जिनका रोजगार के साथ देश की विकास की दर 12 प्रतिशत तक ले जाने में काफी योगदान हो सकता है। इसके लिए पाँच वर्ष का समय मिला है। इनमें टैक्सटाइल और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। जापानी मैनेजमेंट गुरू ने कहा कि वे चीन में भी इसी तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं और दोनों को ही इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में सिक यूनिट को बचाने में भी मदद मिलेगी।

दाएँ से प्रोफेसर शोबी शीबा, डॉ. संजय जी. ढाड़े व डॉ. शेखर चौधरी

आईआईटी-आईआईएम आरक्षण लागू करेंगे

कानपुर (कासं)। आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. संजय गोविंद धांडे और आईआईएम कोलकाता के निदेशक डा. शेखर चौधरी ने बुद्धवार को कहा कि दोनों संस्थान सरकार के आरक्षण सम्बंधी फैसले को मानेंगे। गठित समितियों ने तीन चरणों में इसे लागू करने की संस्तुति की है। संस्थानों को कोई ऐतराज नहीं है। संस्थानों की पहचान देश विदेश में इसलिए नहीं है कि यहाँ कितने छात्र पढ़ते हैं बल्कि इसलिए है कि यहाँ की शिक्षा में क्वालिटी है। इस पर कोई असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। प्रो.धांडे ने कहा कि जब सीटें बढ़ाई गई थीं तो भी इसी तरह की बातें हुई थीं लेकिन सबकुछ सामान्य ढंग से हो गया। जिन शोध संस्थानों को आरक्षण से मुक्ति दी गई है उनकी वजह कुछ और है।